Anveshan (अन्वेषण): A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 3, Issue 1 – 2019

पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका

KESHAV PATEL*

ओम द्यौः शांति रंतरिक्षम्शांतिः पृथिवीशांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांतिरेधि।

-शुक्ल यजुर्वेद **36/1711**

वर्तमान से कुछ वर्ष पूर्व जब कभी पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे दिलों-दिमाग पर आती थी, तो लोगों के मन-मस्तिष्क पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की समस्या से निदान पाने की बात चलती रहती थी, लेकिन वर्तमान वैश्विकरण के दौर में जब विकास ही अंधी दौड़ ही सभी देशों के लिए आवश्यक हो गया है, तो पर्यावरण संरक्षण की बात के वक्त प्रदूषण की समस्याएं बहुत ही जटिल हो चुकी है। आज हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और पटाखों के साथ उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या प्रदूषण को बढ़ावा देने में आम हो चली है। अगर हम वर्तमान में भारत के परिदृश्य में पर्यावरण प्रदूषण से निजात के बारे में विचार करते है, तो हमें दीपावली के वक्त जलने वाले ज्वलनशील और खतरनाक पटाखों पर रोक के लिए सोचना आज के परिदृश्य में आवश्यक हो चला है। पर्यावरण में फेल रहे प्रदूषण के लिए केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए देश के नागरिक भी जिम्मेदार है, जो पर्यावरण के लिए अपने उत्तर दायित्वोंका निर्वहन नहीं कर रहे है। देश में करोड़ों रूपये विस्फोटक ज्वलनशील पटाखों आदि पर उठा दिए जाते है, जो प्रदूषण के लिए अहम जिम्मेदार होते है। इन पैसों का उपयोग अगर दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर को निर्मल बनाने में किया जाएं, तो स्वच्छ वायु में सांस लिया जा सकता है। लोगों की सोच में खोट होने की वजह से देश में पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इन पटाखों में विषैले रसायन और सीसा आदि होता है, जो पर्यावरण में घुलकर वातावरण को प्रभावित करने का कार्य कर रहे है। दिल्ली जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण की वजह पटाखे ही नहीं खेतों की पराली जलाने और मोटर वाहन आदि भी बराबर रूप से जिम्मेदार कहे जा सकते है। खेत की पराली जलाने के मामले में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल देश के लिए नासूर साबित हो रहे है। राष्ट्रीय स्तर पर सालाना नौ करोड़ टन से अधिक पराली खेतों में जलाई जाती है, जिसकी वजह से पर्यावरण के नुकसान के साथ मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित होती है। राज्य सरकारें हर फसली सीजन में अपना घर फूंक तमाशा देखने का कार्य करती आ रही है, जिसके कारण स्थिति यह उत्पन्न होने की कगार पर आ चुकी है, कि सोना उगलने वाली धरती बांझ बनने की कगार पर है, और वायु प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इन सभी तरह के वायु प्रदूषण के जिम्मेदार घटकों से निपटने के लिए न सरकार कोई ठोस कदम उठाती दिख रही है, और न ही जनता अपने आप में इस भयावह मुसीबत की निजात के बारे में कोई सुध लेती दिख रही है।

खेती और किसानों के लिए अहम पराली को संरक्षित करने के बाबत बनाई गई राष्ट्रीय पराली नीति भी राज्य सरकारों के ठेंगा पर दिख रही है। गेहूं, धान और गन्ने की पत्तियां सबसे ज्यादा जलाई जाती है। अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों को मिलाकर सालाना 50 करोड़ टन से अधिक पराली निकलती है उम्मीदों से भरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में छह करोड़ टन पराली में से 2.2 करोड़ टन पराली जलाई जाती है। इसी तरह पंजाब में पांच करोड़ टन में से 1.9 करोड़ और हरियाणा में 90 लाख टन पराली जलाई जाती है।

*Research scholar. MGCGVV Chitrakoot. ***Correspondence E-mail Id:*** editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-4044**

अनुमानित आंकडें के अनुसार सिर्फ एक टन पराली जलाने से 5.5 किग्रा नाइट्रोजन, 2.3 किग्रा फास्फोरस, 25 किग्रा पोटेशियम व 1.2 किग्रा सल्फर पराली जलाने से प्रति वर्ष खेत से नष्ट हो जाते है। इसके कारण कई तरह के सूक्ष्म पौष्टिकता भी खेत से नष्ट हो जाती है, और वायु प्रदूषण के घटक के रूप में सहायता प्रदान करती है। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण और नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पराली नीति बनाई, जिसे राज्यों को सख्ती से लागू करने को कहा गया, लेकिन इसका अमल न के बराबर प्रतीत होता है। परली नीति पर अमल के लिए विभिन्न कृषि, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी-अपनी तरफ से राज्यों को वित्तीय मदद पहुंचाने का प्रावधान है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से अन्न के अलावा अन्य निकलने वाले पदार्थ भी उपयोगी होते है। अतः पराली का उपयोग पशुचारा, कंपोस्ट खाद बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर बनाने, पेपर बोर्ड बनाने आदि में इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकारों को उचित और सकारात्मक पहल करने की जरूरत है, जिससे समय रहते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। वर्तमान स्थिति में वातावरण में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण को जानने से पहले इसके जड़ की बातें मालूम होना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः-

पर्यावरण होता क्या है?

पर्यावरण के अंतर्गत हम जीव-जंतु, पहाड़, जल, वायु, प्रकाश आदि को शामिल कर सकते है, जो मानव जीवन के साथ-साथ इस धरा पर निवास करने वाली सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को पारिभाषित करते हुए कहा गया, कि पर्यावरण में एक तरफ पानी, वायु और भूमि और उनके मध्य अंतः संबंध होते है, और दूसरी तरफ मानवीय प्राणी, पेड़-पौधे आदि होते है। भारत में प्राचीन काल में ही कौटिल्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी।

ग्लोबल वार्मिंग क्या है?

वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा हे। जिसके कारण 2050 तक सूर्य के औसत तापमान में 2 डिग्री की बढोत्तरी देखी जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण वातावरण में भारी उथल-पुथल होने की आशंका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, जिससे तटीय इलाके वाले देश जैसे इंडोनेशिया, जापान,वियत नाम और अन्य देश पीड़ित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचने के लिए 120देशों की बैठक में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार अगर दुनिया की कुल आमदनी का तीन प्रतिशत हिस्सा भी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने पर खर्च किया जायेगा।

मीड़िया की भूमिका

इस धरा पर अभी तक न जाने कितनी सभ्यताएं उदित हुई और खत्म हो चुकी इसका विवरण मानव जीवन में नहीं पता चला। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सामाजिक वातावरण में जहर घुल रहा है। जिससे बचाव में मीडिया अपना अहम योगदान कर रही है। मीड़िया का वह चाहे जो भी माध्यम हो, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव और उसके खिलाफ जागरूक करने के लिए परंपरागत माध्यमों आदि के द्वारा ग्रामीण इलाकों आदि में अशिक्षित जनता को जागरूक करने की कोशिश प्राचीन समय से चल रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से बचाव के लिए टीवी चैनलों और रेड़ियो पर समय-समय पर जनहित से जुड़े विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम मीडिया करती आ रही है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म आदि को शामिल किया जा सकता है। रेडियो

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044

के माध्यम से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का प्रसारण होता है। इसके जरिये सामान्य जन जागरण तक पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा आदि का प्रसारण समय पर किया जाता रहता है। पेड़ लगाओ अभियान आदि की जन जागरूक जानकारियों की जानकारी से लोगों को अवगत कराया जाता रहता है। भारत में मुम्बई में रेडियो क्लब द्वारा जून 1923 में प्रथम बार प्रसारण हुआ। आकाशवाणी अपने लोगो आकाशवाणी, लोक वाणी, जन वाणी के मुताबिक लोगों को शिक्षित करने के साथ समय-समय पर पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानि के बारे में बताकर लोगों का ज्ञान बढ़ाने का कार्य करता है। वर्तमान समय में रेडियो पर्यावरण संरक्षण, उसकी नीतियों से जनता को अवगत करने का काम तेजी से करती आ रही है।

टेलीविजन का महत्व

दूरदर्शन अपने शुरुआती दौर से ही समाज को शिक्षित करने के साथ वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जनता को अवगत कराता आ रहा है। स्टार प्लस पर सत्यमेव जयते कार्यक्रम के द्वारा समाज में पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से जनता को बताया गया है। टेलीविजन का पर्यावरण की समस्या से निपटने का प्रयास वास्तव में सराहनीय है। वह समय पर ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत करता रहता है, जिससे लोगों में पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली व्याधियों से अवगत कराया जा सकें। टेलीविजन ने कचरे और अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, जल संरक्षण का मुद्दाहमेशा से उठाती आ रही है।

आज वर्तमान दौर में विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विकट स्थिति में नजर आ रही है। 2014 में ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव के कारण उत्तराखंड में हुए भयावह तबाही की खबर मीडिया ने दिखाई थी, और ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की अगर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की दिशा में उचित कदम नहीं उठाया जाता है, तो उत्तराखंड की भांति ही आने वाले समय में लगभग सभी पहाडी और तलहटी क्षेत्र अपना अस्तित्व खो देंगे। फिल्में समाज का दर्पण होती है। उसी तर्ज पर काम करते हुए विभिन्न डायरेक्टरों ने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लोगों का ध्यान खिंचने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों आदि का निर्माण किया जा चुका है, और यह दौर जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में 20 वीं सदी के शुरूआत के समय से ही मीडिया अपना योगदान दे रही है। रूसी मीडिया के क्षेत्र में हरियाली के लिए गिल्ड के द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय माना जा सकता है। 1996 में गिल्ड द्वारा पर्यावरण के विरूद्ध रूसी जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,जिसमें के पर्यावरणमुद्दे और पारिस्थितिक तंत्र को लेकर विशेष कवरेज किया गया था।

मीडिया के द्वारा सन् 2002 में प्राकृतिक संसाधन के उचित उपयोग जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न हो इसके लिए पारिस्थितिक-2002 के नाम से भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रकाश किरणों की व्यवस्था के प्रति लोगों का ध्यान लगाना निश्चित किया गया था, जिस उद्देश्य को सकारात्मक पहलू के रूप में जनता का पहुंचाने का काम बखूबी से मीडिया ने अदा किया। इस प्रतियोगिता के उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जनता में जागरूकता, पर्यावरण में स्थानीय सरकार का योगदान और जमीन की घटती उर्वरता के प्रति जनता में प्रभावशाली विचार का प्रसारण मीडिया ने किया, जिससे लोगों के दिलो-दिमाग पर पर्यावरण जागरूकता को लेकर सजग होने की कुछ चेष्टाजाग्रत हुई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय समाचार पत्रों के शामिल होने की संख्या लगभग 15 के करीब थी।

सोशल साइट्स का महत्व

साल 2016 से अमेरीका को पीछे छोडने हुए भारत , चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है। (Patel, 2017)2020 तक भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 73 करोड़ होने का अनुमान है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के उपयोग

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044

में भी हम पीछे नहीं हैं। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 87 प्रतिशत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। (PTI, 2019) ऐसे में सोशल मीडिया पर पर्यावरण से जुड़ी चर्चा और ग्रुप बहुतायत रूप में अस्तित्व में हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विकराल रूप लेने के साथ ही उसके खिलाफ जन चेतना जलाने और जागरूकता फैलाने के क्षेत्र में सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा है। वह भी पर्यावरण और प्रदूषित होते पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए मुहिम चलाने का कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया के साथ इंटरनेट पर तमाम तरीके के ऑनलाइन न्यूज पेपर और वेबसाइट जैसे कि, ग्रीन है किरण है, जो खतरनाक हो रहे प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जाग्रत कर रहा है की वह स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी बातों से जुडकर देश और समाज की जनता को खुशहाल जीवन प्रदान कर सके। सोशल मीडिया में एम-स्वास्थ्य जैसी एप उपलब्ध है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की समस्याओं के प्रति समर्पित होकर लोगों को बचाव का काम करता है।

प्रिंट मीडिया की भूमिका

वर्तमान दौर में बढ़ती वैश्विकरण के दौर में जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तेजी से बढती जा रही है, उससे बचाव और जागरूक करने का काम प्रिंट माध्यम अच्छी तरीके से निभा रहा है। भारत जैसे देश में बिजली के अभाव और गरीबी के कारण अभी भी दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीविज़न और इंटरनेट की पहुंच न होने के कारण से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया अपना अहम योगदान दे सकता है। जिसपर वह शत-प्रतिशत खरा उतरते हुए विज्ञापनों, लेखों, पोस्टरों और पर्यावरणविद् से साक्षात्कार लेकर पर्यावरण प्रदूषण से समाज और देश को बचाने के लिए आह्वान करते रहते है। प्रिंट माध्यम के द्वारा ही पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ आदि के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते है। गांव कनेक्शन जैसे अखबारों ने इस कडी में एक बड़ा काम किया है। अख़बार विगत सालों में लोगों के बीच पर्यावरण और जुडे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में अहम भूमिका निभाई है। मई 2000 में हुई पत्रकारों की एक संगोष्ठी में पर्यावरण जागरूकता का मुद्दा फिर से तूल पकड़ा, और पर्यावरण निरक्षता के उन्मूलन पर चर्चा हुई और सरकार कई कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया

परंपरागत मीडिया का महत्व

परंपरागत मीडिया ग्रामीण और आदिवासी समाज के बीच सीधा संवाद का काम करती है। इस माध्यम में कठपुतली नौटंकी, लोक नृत्य, नुक्कड नाटक आदि आते है। इन माध्यमों के द्वारा उन क्षेत्रों में आसानी से पर्यावरण के प्रति जागरूकता के संदेश प्रचारित किए जा सके जहां पर आधुनिक संसाधनों की पहुंच अत्यंत कम हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत में लगातार प्रयास किए जा रहे है। समय-समय पर मीडिया ने जनमानस द्वारा किये जा रहे आंदोलनों को प्रमुखता से अपने संस्थानों में स्थान दिया है जिसके वजह से ही ये आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हो पाये और लोग पर्यावरण के प्रति सजग हो सके , इन आंदोलनों में चिपको आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, मूक घाटी आंदोलन और भोपाल गैस त्रासदी आंदोलन प्रमुख है

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है, कि संचार क्रांति के आने के बाद से पर्यावरण प्रदूषण से बचाव में मीडिया का योगदान काफी सराहनीय रहा है। जैसे-जैसे संचार के नये-नये आयाम विकसित हो रहे है, लोगों में विचारों और ज्ञान का प्रवाह करने में आसानी होती जा रही है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को सचेत करने में मीडिया अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति ढंग से अदा कर रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. Patel, K. (2017, 01 01). Lok Sabha 2014, Narendra Modi And Social Sites. International Journal of Recent Advances in Psychology & Psychotherapy, 01(01). Retrieved 02 27, 2019

[2]. PTI. (2019, 03 06). nternet users in India. Retrieved from economictimes.india times.com.

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044